Dollar Digest

चक्रव्यूह

अर्थव्यवस्था को समझें, बेहतर भविष्य बनाएं।

मैक्रोइकॉनॉमिक्स की आसान भाषा में किताब

80% हिंदी | 20% ENGLISH

Shrey Bhartia

A DOLLAR DIGEST COMMUNITY OUTREACH INITIATIVE

एक बात पहले

यह किताब मैंने इसलिए नहीं बनाई कि तुम exam में अच्छे marks लाओ. मैंने यह इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि economy को समझना हर किसी का हक है. सिर्फ उनका नहीं जो बड़े schools में पढ़ते हैं या जिनके घर में business है.

जब तुम सब्जी लेने जाते हो और टमाटर ₹10 की जगह ₹60 का मिलता है, तो क्यों? जब news में कहते हैं कि dollar महंगा हो गया, तो इसका तुम्हारी life पर क्या असर पड़ता है? जब कोई कहता है कि India एक fast growing economy है, तो उसका क्या मतलब है और क्या यह सच में सबके लिए है?

इन सवालों के जवाब इस किताब में हैं. बिना complicated words के, बिना boring lectures के. हर चीज़ को उन चीज़ों से जोड़ा है जो तुम रोज़ देखते हो, छूते हो, खरीदते हो. जो families Gulf में काम करती हैं, जो लोग daily wage पर निर्भर हैं, जो किसान हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, सबकी story इस economy में है.

पढ़ते वक्त अपने आसपास की दुनिया से connect करते रहो. और अगर कोई सवाल आए तो उसे कहीं लिख लो.

- Shrey Bhartia, Dollar Digest

इस किताब में क्या है

भाग 1 : पैसा क्या होता है?

भाग 2 : बाज़ार, Demand और Supply

भाग 3 : महंगाई और Interest Rates

भाग 4 : भारत की Economic कहानी

भाग 5 : India की बड़ी Economic Moments

भाग 6 : Resources, Decisions और Trade-offs

भाग 7 : Government और Economy

भाग 8 : दुनिया से India का Connection

भाग 9 : खबर पढ़ना सीखो

Glossary : मुश्किल शब्दों के आसान मतलब

भाग 1

पैसा क्या होता है?

Economy की बात करें और पैसे की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन पहले एक सवाल. पैसा आया कहाँ से? क्या हमेशा से था? अगर नहीं था, तो इससे पहले लोग कैसे काम चलाते थे?

इन सवालों के जवाब जानना ज़रूरी है क्योंकि जब तुम पैसे की history समझते हो, तो तुम यह भी समझते हो कि पैसा actually क्या है और इसकी value क्यों होती है.

Barter System: पैसे से पहले की दुनिया

बहुत पहले, जब coins और notes नहीं थे, लोग चीज़ें आपस में बदलते थे. इसे barter system कहते हैं. एक किसान के पास गेहूं है. एक दूसरे के पास मिट्टी के बर्तन हैं. दोनों को एक-दूसरे की चीज़ चाहिए. वो exchange करते हैं. Simple.

लेकिन यह उतना simple नहीं था जितना लगता है. Barter की एक बड़ी problem थी जिसे economists double coincidence of wants कहते हैं.

Imagine करो: एक किसान है जिसके पास गेहूं है और उसे बाल कटवाने हैं. वो नाई के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, तुम मेरे बाल काटो. नाई बोलता है: भाई, मेरे घर में पहले से बहुत गेहूं है. मुझे नहीं चाहिए. मुझे तो कपड़े चाहिए.

अब किसान कपड़े वाले के पास जाता है. कपड़े वाला कहता है: मुझे गेहूं नहीं, मुझे तेल चाहिए. किसान फिर तेल वाले के पास जाता है...

यह chain कहाँ खत्म होगी? पता नहीं. Barter में बहुत ज़्यादा time और energy waste होती थी. और यह भी problem थी कि अगर किसी को आधा बैल चाहिए हो तो? बैल को आधा नहीं कर सकते.

इसीलिए पैसे का idea आया. एक ऐसी चीज़ जिसे सब value दें. जो divisible हो, यानी छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जा सके. जो easily carry हो सके. जो समय के साथ खराब न हो.

पैसा कैसे **evolve** हुआ?

शुरुआत में लोगों ने shells, stones, और beads use किए. फिर metals आए, particularly gold और silver, क्योंकि वो rare थे, टिकाऊ थे, और divide किए जा सकते थे. India में Vedic times में nishka और mana जैसे gold और silver weights currency के रूप में use होते थे.

फिर coins आए. India में पहले coins करीब 600 BCE में Mahajanapada period में मिलते हैं. इन्हें punch-marked coins कहते हैं. Mauryan empire में Chandragupta Maurya के समय में एक organized monetary system था.

Paper money बाद में आई. China में 7th century में. India में British colonial period में paper currency आई जो RBI ने eventually manage की. और आज digital money है, जो physically exist भी नहीं करता, सिर्फ numbers हैं किसी screen पर.

पैसे की **value** कहाँ से आती है**?**

₹100 का note कागज़ का एक टुकड़ा है जिसकी manufacturing cost शायद ₹2-3 है. उसमें ऐसा क्या है कि दुकानदार उसके बदले तुम्हें ₹100 की value का सामान देता है?

जवाब है: trust और collective agreement. हम सब agree करते हैं कि यह note value रखता है. Reserve Bank of India ने इसे issue किया है. Government ने इसे legal tender declare किया है. इसका मतलब है कि कोई भी इसे payment के रूप में refuse नहीं कर सकता.

Note पर लिखा होता है: 'मैं धारक को _____ रुपये अदा करने का वचन देता हूँ.' यह RBI Governor का वचन है. पैसा basically एक promise है.

> **Class में Example:** Imagine करो तुम्हारी class में teacher ने एक नया system बनाया. अब से जो भी अच्छा काम करेगा उसे 'stars' मिलेंगे. Stars से canteen में खाना खरीद सकते हो, library में books ले सकते हो. धीरे-धीरे stars class की currency बन गई. उनमें value इसलिए है क्योंकि सब उसे मानते हैं. अगर एक दिन teacher ने कहा कि अब stars काम नहीं करेंगे, तो वो worthless हो जाएंगे. पैसे के साथ भी यही है: value trust में है, कागज़ में नहीं.

क्या **government** जितना चाहे उतना पैसा **print** कर सकती है**?**

यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है. अगर देश में गरीबी है, poverty है, तो बहुत सारा पैसा print करके सबको दे दो. Problem solved. Simple लगता है ना?

लेकिन यह उतना simple नहीं है. ज़्यादा पैसा print करने से वो पैसा कमज़ोर हो जाता है. एक example से समझो:

मान लो एक छोटे से गाँव में 10 लोग हैं. उस गाँव में कुल 100 apples हैं और कुल ₹100 currency है. तो एक apple की average price ₹1 है. अब government ने ₹100 और print करके सबको बाँट दिए. अब गाँव में ₹200 हैं. लेकिन apples अभी भी 100 हैं. तो एक apple की price? ₹2 हो गई. पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन खरीद पाओगे उतना ही.

यह inflation है. Prices बढ़ गईं. और जिन लोगों के पास पहले से savings थी, उनकी savings की real value कम हो गई.

Zimbabwe में 2008 में यही हुआ. Government ने बहुत ज़्यादा पैसा print किया. Inflation इतनी बढ़ी कि एक bread के लिए billions of dollars लगते थे. लोग wheelbarrows में notes भरकर दुकान जाते थे. वो currency worthless हो गई. इसे hyperinflation कहते हैं.

पैसा कैसे चलता है और **economy** क्यों **grow** करती है**?**

पैसा कभी एक जगह नहीं रहता. वो हमेशा घूमता रहता है और इसी घूमने से economy जीवित रहती है और बढ़ती है.

तुम एक cup chai खरीदते हो ₹15 में. वो ₹15 chai wale के पास जाते हैं. Chai wala उन पैसों से अपनी दुकान का किराया देता है. मकान मालिक उन पैसों से दूध खरीदता है. Doodhwala उन पैसों से अपने बच्चे की school fees भरता है. School उन पैसों से teachers को salary देता है. Teacher उन पैसों से सब्जी खरीदता है. Sabzi wali उन पैसों से अपनी बेटी की शादी में contribute करती है...

एक ₹15 का coin कितनी जगह काम करता है. जितना ज़्यादा यह chain चलती है, उतना ज़्यादा सब लोगों का काम होता है. जब यह chain रुकती है जैसे COVID lockdown में, economy को बहुत नुकसान होता है.

Economists इसे velocity of money कहते हैं. पैसा जितनी तेज़ी से hands बदले, economy उतनी active होती है. इसीलिए government recessions में spending बढ़ाती है, ताकि chain दोबारा शुरू हो.

> **Savings का Role:** अगर सब अपना पैसा सिर्फ तकिये के नीचे रखें और खर्च न करें, तो chain रुक जाएगी. लेकिन अगर bank में रखें, तो bank उसे किसी business को loan देती है जो नई jobs create करता है. इसीलिए savings का भी economy में role है, बशर्ते वो productive investment में जाए.

Digital Money का ज़माना

आज हम जिस दुनिया में हैं, वहाँ money increasingly digital हो रही है. UPI, credit cards, net banking. Physical cash का use कम होता जा रहा है. India में 2016 से पहले 78% transactions cash में थे. 2023 में यह करीब 40% पर आ गया. यह बहुत बड़ा shift है सिर्फ कुछ सालों में.

Digital money की advantages हैं: easily traceable है जिससे tax evasion मुश्किल होती है. Transaction cost कम है. Convenience बहुत है. India के UPI system ने prove किया है कि digital payments को mass adoption मिल सकती है अगर system simple हो.

लेकिन challenges भी हैं. जो लोग smartphone नहीं रखते या internet नहीं है उनके लिए digital money accessible नहीं है. Cyber fraud बढ़ा है. और अगर system down हो जाए तो transaction रुक जाती है. Cash की अपनी reliability है.

पैसे की **Types:** जो तुम रोज़ **Deal** करते हो

Currency Notes और Coins: Physical cash जो RBI issue करती है. Legal tender है. किसी को refuse करने का अधिकार नहीं.

Bank Deposits: जो पैसा bank में है वो भी money है. Transfer, withdraw, या pay कर सकते हो. India में Deposit Insurance ₹5 lakh तक protect करती है.

Mobile Wallets: Paytm, PhonePe, Google Pay में जो balance होता है वो digital money है. Regulated है लेकिन bank deposit से थोड़ा अलग है.

Credit: जब bank तुम्हें loan देती है, वो नई purchasing power create करती है. इसीलिए banks का economy में बहुत power होता है और उन्हें carefully regulate करना ज़रूरी है.

> **Interesting Fact:** UPI में 2023 में जितनी transactions हुईं, उनकी total value India की GDP के करीब 90% थी. इसका मतलब है India की economy का एक बड़ा हिस्सा अब digitally transact हो रहा है. 5 साल पहले यह सोचना भी मुश्किल था.

भाग 2

बाज़ार, Demand और Supply

जब भी तुमने कुछ खरीदा या बेचा, तुम एक market का हिस्सा बन गए. Market का मतलब सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ सब्जी बिकती है. Market कोई भी जगह है जहाँ buyers और sellers मिलते हैं और एक price पर agree करते हैं.

तुम्हारी local sabzi mandi एक market है. Flipkart एक market है. Auto-rickshaw stand एक market है जहाँ drivers और passengers मिलते हैं. IPL में cricket players के contracts के लिए भी एक market है. दुनिया में oil की खरीद-बिक्री के लिए एक global market है.

Demand को गहराई से समझो

Demand का मतलब है: लोग किसी चीज़ को कितना खरीदना चाहते हैं, और किस price पर. यह एक simple idea है लेकिन इसके कई dimensions हैं.

Law of Demand: Price जितनी कम होगी, demand usually उतनी ज़्यादा होगी. अगर onion ₹10 kilo हो तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे. ₹100 kilo हो तो कम खरीदेंगे. यह common sense भी है.

लेकिन demand सिर्फ price से नहीं बदलती. इसे affect करने वाले और factors:

> Income: अगर तुम्हारे घर की income बढ़ जाए तो तुम ज़्यादा और बेहतर चीज़ें खरीदोगे. पहले cycle थी, अब bike. पहले local दुकान, अब mall. India में middle class बढ़ रही है, इसीलिए consumer goods की demand बढ़ रही है.
>
> Substitutes: अगर onion बहुत महंगी हो जाए, तो लोग garlic या ginger से ज़्यादा काम चलाएंगे. अगर petrol महंगा हो, तो CNG या electric vehicles की demand बढ़ती है. Substitute goods वो होते हैं जो एक-दूसरे की जगह use हो सकते हैं.
>
> Taste और Fashion: जब cricket world cup होता है तो India की jersey की demand बढ़ जाती है. Diwali से पहले lights और sweets की demand बढ़ती है. Eid पर clothes और vermicelli. यह seasonal और cultural demand है.
>
> Future Expectations: अगर लोगों को लगे कि कल petrol और महंगा होगा, तो वो आज ही ज़्यादा खरीद लेते हैं. यह panic buying है. COVID में जब लोगों को लगा कि lockdown आएगा, उन्होंने groceries stockpile कर ली. Demand artificially बढ़ गई और shelves खाली हो गए.

Supply को गहराई से समझो

Supply का मतलब है: sellers के पास कितना है बेचने के लिए, और किस price पर वो बेचने को तैयार हैं.

Law of Supply: Price जितनी ज़्यादा होगी, sellers उतना ज़्यादा supply करना चाहेंगे. अगर onion ₹100 kilo बिक रही है, तो ज़्यादा farmers onion उगाएंगे. अगर ₹10 kilo बिक रही है, तो कई farmers दूसरी crops की तरफ जाएंगे.

Supply को affect करने वाले factors:

Production Cost: अगर fertilizer, water, labour, या electricity महंगी हो जाए, तो farming expensive हो जाती है. Sellers को वो cost price में add करनी पड़ती है या production कम करना पड़ता है. यही reason है कि जब oil prices बढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी होती हैं.

Technology: बेहतर seeds और machines से same ज़मीन पर ज़्यादा produce होता है. India में Green Revolution इसीलिए इतनी successful थी. 1960s में Dr. MS Swaminathan की team ने high-yield wheat और rice varieties develop कीं. Wheat production 1965 में 10 million tonnes था, जो 1972 तक 27 million tonnes हो गया. Technology ने supply dramatically बढ़ाई.

Weather: India में crops बहुत हद तक monsoon पर depend करती हैं. अच्छी बारिश मतलब अच्छी supply. Drought या बाढ़ मतलब कम supply. इसीलिए India में हर साल monsoon forecast इतनी important होती है.

Case Study: Onion Crisis 2019-20

2019-20 में India में onion की कीमत ₹20 से बढ़कर ₹150-200 per kilo हो गई. यह एक ऐसी vegetable है जो लगभग हर Indian dish में जाती है. Families परेशान थीं. Politicians को parliament में सवाल पूछे गए.

क्या हुआ था? उस साल Maharashtra और Karnataka में पहले drought था फिर बेमौसम भारी बारिश हुई. Onion की खड़ी फसल बर्बाद हो गई. Nashik जो India का onion capital है, वहाँ supply बहुत कम हो गई. लेकिन demand वही रही क्योंकि हर घर में onion की ज़रूरत है.

Supply कम, demand same: result था prices का आसमान छूना. इसे economists supply shock कहते हैं.

Government ने क्या किया? Egypt, Turkey, और Afghanistan से onion import की. Domestic export पर ban लगाया ताकि जो stock था वो India में ही रहे. Hoarding के खिलाफ action लिया. धीरे-धीरे situation normal हुई.

लेकिन इस episode ने एक बड़ा सबक दिया: India की agricultural supply एक weather event से severely affect हो सकती है. यही reason है कि food security policy और better storage facilities इतनी ज़रूरी हैं.

Demand और Supply कैसे मिलते हैं?

Market में price वहाँ तय होती है जहाँ demand और supply बराबर होती हैं. इसे market equilibrium कहते हैं.

अगर price बहुत ज़्यादा हो, तो supply ज़्यादा होगी लेकिन demand कम. Sellers के पास unsold stock रहेगा. वो price कम करेंगे.

अगर price बहुत कम हो, तो demand ज़्यादा होगी लेकिन supply कम. Shortage होगी. Buyers ज़्यादा price देने को तैयार होंगे. Price ऊपर जाएगी.

Market naturally equilibrium की तरफ move करता है. यह हर moment होता है, हर market में. तुम्हारी sabzi mandi में भी, oil की global market में भी.

Competition का power

Jio ने 2016 में India का telecom market बदल दिया. जब Jio launch हुआ, Mukesh Ambani ने announce किया: free voice calls, सस्ता data. Airtel, Vodafone, और Idea को अपनी prices dramatically कम करनी पड़ीं.

2016 से पहले 1 GB mobile data का cost था ₹250-300. Jio के बाद वही 1 GB ₹10-15 में मिलने लगा. India में data सबसे सस्ता हो गया दुनिया में. Millions of people जिनके पास पहले affordable internet नहीं था, वो online आ गए. UPI transactions बढ़े. Online education possible हुई. यह सब competition के कारण हुआ.

> **Real World Observation:** अगली बार जब तुम market जाओ, देखो कि जहाँ ज़्यादा competition है वहाँ quality बेहतर है और price कम है. जहाँ monopoly है, यानी एक ही seller है, वहाँ price ज़्यादा है और quality पर कम ध्यान होता है. यह theory नहीं है, यह तुम्हारे आसपास हर रोज़ दिखता है.

Market के Types: सब एक जैसे नहीं होते

Perfect Competition: कई buyers, कई sellers, similar products. Sabzi mandi इसके करीब है. Price demand-supply से तय होती है. कोई एक seller control नहीं कर सकता.

Monopoly: एक ही seller. BSNL एक time पर telecom में monopoly था. Jio आने से पहले data prices बहुत ज़्यादा थीं. Competition न हो तो quality कम और price ज़्यादा होती है.

Oligopoly: कुछ बड़े players जैसे Indian telecom में Jio, Airtel, Vi. तीनों एक-दूसरे की moves देखते हैं. एक price बदले तो बाकी भी change करते हैं.

Price Discrimination: एक ही चीज़, अलग Price

Train में same destination के लिए tatkal ticket ज़्यादा महंगी होती है. Movies में morning shows सस्ते होते हैं. Airlines में जितनी जल्दी book करो, उतना सस्ता. यह price discrimination है.

Sellers जानते हैं कि सब customers की willingness to pay अलग होती है. Urgent traveler ज़्यादा pay करेगा. Flexible person सस्ता option लेगा. इस तरह seller अपना total revenue maximize करता है. यह unfair नहीं, यह smart business है.

Black Market: जब Rules तोड़े जाते हैं

जब government किसी चीज़ की price fix करती है या उसे restrict करती है, तो लोग कभी-कभी black market की तरफ जाते हैं जहाँ वो चीज़ illegally मिलती है.

World Cup tickets official में ₹2000, black market में ₹20,000. Onion crisis में government की fixed price थी, लेकिन कुछ traders ने ज़्यादा price पर बेचा. यह economic law है: अगर official price और actual willingness to pay में बड़ा gap हो, तो कोई उसे fill करने की कोशिश करता है.

> **Jio Revolution:** 2016 में Jio launch हुआ. उससे पहले 1 GB data ₹250-300. बाद में ₹10-15. यह competition का power है. Millions of Indians जिनके पास internet नहीं था, वो online आए. UPI बढ़ी. Online education possible हुई. Online shopping बढ़ी. एक company के एक decision ने पूरे market को बदल दिया.

भाग 3

महंगाई और Interest Rates

Inflation यानी महंगाई शायद वो economic concept है जो सबसे ज़्यादा हर घर में feel होती है. जब दादी कहती हैं कि उनके ज़माने में एक rupee में चाय, बिस्कुट, और newspaper मिलते थे, वो inflation की बात कर रही हैं. जब तुम्हारे घर में हर month ये complaint होती है कि prices बढ़ गई हैं, वो inflation है.

Inflation को exactly कैसे measure करते हैं?

India में inflation को मुख्यतः दो तरीकों से measure किया जाता है:

CPI यानी Consumer Price Index: यह एक typical family जो चीज़ें खरीदती है उनकी average price को track करता है. इस basket में food, clothing, housing, transport, education, और healthcare शामिल हैं. RBI मुख्यतः CPI देखती है.

WPI यानी Wholesale Price Index: यह wholesale level पर prices track करता है, यानी factories और wholesale markets में. यह usually CPI से पहले change होती है.

अगर CPI 6% है, तो इसका मतलब है उस basket का जो एक साल पहले ₹100 में आता था, वो अब ₹106 में आता है.

Inflation क्यों होती है?

Demand-pull inflation: जब economy में बहुत demand हो और supply उसे पूरा नहीं कर पाए. COVID के बाद जब lockdown खुला, लोगों में बाहर जाने, खाने, travel करने की demand एकदम बढ़ गई. Restaurants, hotels, airlines सबकी demand एक साथ आई. Supply उतनी तेज़ नहीं बढ़ी. Prices बढ़ीं. इसे pent-up demand कहते हैं.

Cost-push inflation: जब production expensive हो जाए और वो cost prices में pass हो. अगर petrol महंगा हो जाए, तो:

Trucks महंगे चलेंगे.

Sab kuch transport karna mehnga padega.

Factories में energy cost बढ़ेगी.

Farmer को fertilizer महंगी पड़ेगी.

यह सारी costs consumers तक पहुँचती हैं. इसीलिए जब global oil prices बढ़ती हैं, India में लगभग सब कुछ महंगा होने लगता है.

Monetary inflation: जब market में बहुत पैसा हो. जैसा हमने Part 1 में समझा. Government अगर बहुत पैसा print करे या interest rates बहुत कम रखे, तो बहुत सस्ते loans मिलते हैं. लोग ज़्यादा खर्च करते हैं. Prices बढ़ती हैं.

> **Case Study: 2022 की Global Inflation:** Russia-Ukraine war शुरू हुई 2022 में. Russia दुनिया का बड़ा oil और gas exporter है. Ukraine दुनिया का बड़ा wheat exporter है. War की वजह से supply disrupted हुई. Oil और wheat prices दुनिया भर में बढ़े. India में cooking oil, आटा, और transport सब महंगे हुए. CPI inflation 7-8% तक पहुँची जो RBI की 6% की upper limit से ऊपर थी. एक दूसरे देश की war ने India की kitchen को directly affect किया.

Inflation का असर अलग-अलग लोगों पर अलग होता है

यह बात बहुत important है जो अक्सर ignore होती है. Inflation सबको equally affect नहीं करती.

जिनके पास fixed salary है जैसे government employees या factory workers, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है. उनकी salary वही रहती है लेकिन चीज़ें महंगी हो जाती हैं.

जिनके पास property, gold, या shares हैं, inflation में उनकी assets की value भी usually बढ़ती है. इसीलिए rich लोगों को inflation से कम नुकसान होता है.

जो poor हैं और सबसे ज़्यादा अपनी income खाने पर खर्च करते हैं, उन्हें food inflation से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है. India में poor families की income का 40-50% food पर जाता है. Rich families का शायद 10-15%.

इसीलिए food inflation को control करना India में एक political और social priority है, not just an economic one.

RBI और Interest Rates

RBI यानी Reserve Bank of India India का central bank है. यह एक bank है जो banks की bank है. आम लोग सीधे RBI से deal नहीं करते. लेकिन RBI के decisions हर किसी की ज़िंदगी को affect करते हैं.

RBI का एक बड़ा काम है: monetary policy manage करना. इसका मतलब है economy में money की supply और cost को control करना.

RBI का सबसे powerful tool है Repo Rate. यह वो rate है जिस पर RBI commercial banks को short-term loan देती है. अगर RBI repo rate बढ़ाए:

Banks को RBI से पैसा लेना महंगा पड़ता है.

Banks अपने customers को loan महंगे देती हैं.

Home loan, car loan, business loan के EMI बढ़ते हैं.

लोग कम loan लेते हैं. कम खर्च करते हैं.

Demand कम होती है. Inflation का pressure कम होता है.

अगर RBI repo rate कम करे, तो उल्टा होता है. Loans सस्ते होते हैं. Business invest करते हैं. Hiring बढ़ती है. Economy grow करती है. लेकिन अगर ज़्यादा हो तो inflation का risk रहता है.

यह एक balancing act है जो RBI हर दो महीने में Monetary Policy Committee की meeting में करती है. इसे दुनिया भर के economists और investors ध्यान से देखते हैं.

> **Real Example: 2022-24:** COVID के बाद जब inflation बढ़ी, RBI ने May 2022 में repo rate 4% से बढ़ाना शुरू किया. कुछ meetings में rate 6.5% तक पहुँचा. इससे home loan EMI कई हज़ार रुपये बढ़ गई. कुछ लोगों ने घर खरीदने के plans रोके. Demand कम हुई. धीरे-धीरे inflation काबू में आई. 2024 में जब inflation comfortable level पर आई, RBI ने rates कम करने शुरू किए ताकि economy को growth के लिए support मिले.

Exchange Rate: Rupee क्यों ऊपर-नीचे होता है?

Exchange rate: 1 US Dollar के लिए कितने rupees देने होंगे. यह भी demand-supply से तय होता है.

अगर foreign investors India में invest करना चाहें, वो dollars लाएंगे, rupees खरीदेंगे. Rupee की demand बढ़ेगी, rupee strong होगा. अगर India बहुत ज़्यादा import करे, हमें ज़्यादा dollars चाहिए, rupee weak होगा.

Weak rupee का नुकसान: Import महंगी होती है. Petrol, oil, electronics सब ज़्यादा costly. Inflation बढ़ सकती है.

Weak rupee का फायदा: Export सस्ती होती है. India का software, medicines foreign buyers को cheaper लगते हैं. Export बढ़ सकता है. IT companies को dollar में payment मिलती है, rupee weak हो तो उन्हें rupees में ज़्यादा मिलता है.

Interest Rates और Daily Life

Savings Account पर bank interest देती है. RBI rate high होने पर savings accounts पर ज़्यादा interest मिलता है, saving incentivize होती है.

Fixed Deposit पर और ज़्यादा interest. India में senior citizens को extra rate मिलता है ताकि उनकी retirement savings grow करें.

EMI: Bike, phone, या appliance loan पर लो, monthly EMI दो जिसमें principal plus interest होता है. Interest rate high हो तो EMI ज़्यादा होती है.

Microfinance: India में बहुत लोगों को formal bank loan नहीं मिलता. Microfinance institutions small loans देती हैं small businesses और self-employed लोगों को. Self Help Groups, specially women के, इसी system पर काम करते हैं. Grameen Bank model पूरी दुनिया में famous है. India में Bandhan Bank इसी microfinance background से आई और एक full bank बन गई.

भाग 4

भारत की Economic कहानी

India एक बहुत बड़ा और बहुत diverse देश है. 140 crore लोग. 28 states और 8 union territories. Hundreds of languages. बहुत अलग climates, cultures, और livelihoods. इन सबको एक साथ देखना और फिर यह समझना कि यह पूरा देश economically कैसे काम करता है, यह fascinating है.

India की economy के तीन बड़े हिस्से

Economists किसी भी economy को तीन sectors में divide करते हैं:

Primary Sector यानी Agriculture: खेती, fishing, mining, और forestry. यह directly nature से resources लेता है. India में करीब 40-45% लोग इस sector पर depend करते हैं. लेकिन GDP में इसका contribution सिर्फ 15-18% है. इस gap को समझना ज़रूरी है: बहुत सारे लोग relatively कम earn कर रहे हैं. यह India की सबसे बड़ी economic challenges में से एक है.

Secondary Sector यानी Manufacturing: Raw materials को process करके finished goods बनाना. Steel mills, car factories, textile units, pharmaceutical companies. इस sector में GDP का करीब 25-28% हिस्सा है. Government का Make in India program manufacturing को बढ़ावा देने के लिए है.

Tertiary Sector यानी Services: यह India का सबसे बड़ा sector है, GDP का 55% से ज़्यादा. IT companies, banking, insurance, healthcare, education, retail, transport, hospitality, सब यहाँ आते हैं. India की IT industry एक global phenomenon है.

Agriculture: India की backbone

India दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा agricultural producer है. हम दुनिया में सबसे ज़्यादा milk, pulses, और spices produce करते हैं. Rice और wheat में भी top producers में हैं.

लेकिन Indian agriculture की कुछ बड़ी problems हैं:

Monsoon dependency: India की करीब 50% agricultural land still rainfall पर depend करती है, irrigation पर नहीं. जब monsoon कमज़ोर होता है, crops कम होती हैं, farmers income कम होती है, rural economy slow होती है.

Small farm size: India में average farm size सिर्फ 1.1 hectare है. छोटे farms में modern technology और machinery use करना economically viable नहीं होता. इससे productivity कम रहती है.

Market access: बहुत से farmers अपनी crops middlemen को बेचते हैं जो उन्हें कम price देते हैं और खुद ज़्यादा margin लेते हैं. Farmers को directly consumers तक पहुँचाने के लिए मंडियों और e-Nam जैसे platforms की ज़रूरत है.

GDP: देश का report card

GDP यानी Gross Domestic Product. एक साल में पूरे देश ने जो भी final goods और services produce कीं उनकी total market value.

> **Easy Example:** एक छोटे से गाँव में 5 लोग हैं. किसान ने ₹10,000 का अनाज उगाया. नाई ने ₹5,000 की services दीं. दूधवाले ने ₹8,000 का दूध बेचा. दर्जी ने ₹7,000 के कपड़े बनाए. Teacher ने ₹6,000 की fees ली. Total: ₹36,000. यही उस गाँव का GDP है. India में यही calculation 140 crore लोगों के लिए होती है, इसीलिए India की GDP $3.5 trillion के आसपास है.

India अभी दुनिया की 5th largest economy है. लेकिन per capita GDP, यानी per person average income, बहुत कम है क्योंकि population बहुत ज़्यादा है. India की per capita income अभी करीब $2,500 per year है, जबकि America की $80,000 से ज़्यादा है.

इसका मतलब यह नहीं कि India poor है. इसका मतलब है India में बहुत लोग हैं और inequality बहुत है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत लोग बहुत कम. Average को देखने से पूरी picture नहीं मिलती.

अलग states क्यों अलग हैं?

India के states में आर्थिक असमानता बहुत बड़ी है. Maharashtra और Goa की per capita income Bihar और Uttar Pradesh से कई गुना ज़्यादा है. क्यों?

History: Mumbai और Chennai जैसे शहर British India में major trade centers थे. Colonial infrastructure, ports, और railways वहाँ पहले बने. यह head start आज भी दिखती है.

Geography: Coastal states trade के लिए better position में हैं. Ports से export-import आसान होता है. Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu इसी कारण industrially developed हैं.

Education और Human Capital: Kerala में literacy rate 96% से ज़्यादा है. Educated population better jobs के लिए qualified होती है. Investment आता है. Kerala की per capita income उसके अनुसार है.

Natural Resources: Irony यह है कि जिन states में सबसे ज़्यादा natural resources हैं जैसे Jharkhand में coal और minerals, वो states often less developed हैं. Resource curse एक real phenomenon है.

Governance: जिस state में better infrastructure, कम corruption, और business-friendly policies हों, वहाँ investment आता है, jobs बनती हैं. Gujarat इसका एक example है जहाँ focused industrial policy ने बड़ा difference किया.

India की IT Industry: एक Miracle Story

India की IT industry की success एक remarkable story है. 1991 में जब economy open हुई, India के engineering graduates को नया opportunity मिला. America और Europe में software professionals की demand थी. India में educated, English-speaking engineers थे जो globally competitive cost पर काम कर सकते थे.

Bangalore जो पहले public sector industries का शहर था, वो India's Silicon Valley बन गया. Infosys, Wipro, TCS जैसी companies global giants बन गईं. आज IT sector India को सालाना $200 billion से ज़्यादा foreign exchange earn करवाता है.

लेकिन IT industry की limitations भी हैं. यह mostly high-skilled, English-speaking workers के लिए है. India के majority workers जो agriculture या informal economy में हैं, उन्हें IT boom का direct benefit कम मिला. यह economic inequality का एक dimension है.

Informal Economy: वो जो GDP में नहीं दिखता

India की GDP में officially वो activity शामिल होती है जो registered और taxed है. लेकिन India में बहुत बड़ी informal economy भी है. Street vendors, small repair shops, domestic workers, daily wage laborers. इनकी activity officially GDP में properly count नहीं होती.

Estimates के अनुसार India की informal economy formal economy के size के करीब है. Informal sector में करीब 90% Indian workers employed हैं. यह लोग economically very vulnerable हैं. No job security, no social benefits, no minimum wage guarantee.

Formalization की ज़रूरत है. Jan Dhan Yojana ने millions of Indians को first time banking system में लाया. Aadhaar से identity verification easy हुई. GST से businesses को formal होने का incentive मिला. यह एक long process है जो India actively pursue कर रही है.

Two India: एक India है Bangalore और Mumbai का जहाँ startups हैं, IT parks हैं, high salaries हैं. दूसरा India है गाँवों का, छोटे शहरों का, informal economy का. Economic policy की सबसे बड़ी challenge यह है कि इन दोनों के बीच की gap कम हो. Growth सिर्फ कुछ pockets में नहीं, wide और inclusive होनी चाहिए.

भाग 5

India की बड़ी Economic Moments

India की economy कभी एक straight line में नहीं चली. बड़े decisions, बड़े झटके, और बड़ी recoveries. इन moments को समझना ज़रूरी है क्योंकि इनसे पता चलता है कि economic decisions का असर कितना real और कितना lasting होता है.

1991: जब India की economy खुली

1991 से पहले India में एक system था जिसे License Raj कहते हैं. हर factory खोलने के लिए, हर product बनाने के लिए, हर machine import करने के लिए government का license चाहिए होता था. हर चीज़ में government का control था. इस system में बहुत corruption था क्योंकि license देना officials के हाथ में था.

1991 में India एक बड़े economic crisis में था. Foreign exchange reserves इतने कम हो गए थे कि India सिर्फ 2 हफ्ते के imports pay करने की capacity में था. India को RBI का gold IMF के पास गिरवी रखना पड़ा. यह बहुत शर्मनाक moment था.

तब Prime Minister Narasimha Rao और Finance Minister Dr. Manmohan Singh ने एक historic decision लिया. Licenses खत्म किए. Economy open की. Foreign companies आ सकती थीं. Import-export आसान हुआ. Rupee को gradually devalued किया ताकि exports competitive हों.

इसके बाद क्या हुआ? Infosys, Wipro, TCS जैसी IT companies global stage पर आईं. Foreign investment बढ़ा. Manufacturing sector grow किया. Middle class expand हुआ. 1991-2011 के बीच 270 million लोग poverty से बाहर निकले. यह India की economy का सबसे बड़ा turning point था.

> सोचो: अगर 1991 में liberalization नहीं होती, तो शायद आज India में वो IT sector नहीं होता जो है. Bangalore को Silicon Valley of India नहीं कहा जाता. Millions of educated Indians को वो opportunities नहीं मिलतीं जो मिलीं. एक policy decision ने एक generation की ज़िंदगी बदल दी.

2016: Demonetization का झटका

8 November 2016 की रात 8 बजे, PM Narendra Modi ने national address में announce किया कि ₹500 और ₹1000 के notes midnight से legal tender नहीं रहेंगे. नए ₹500 और ₹2000 के notes आएंगे.

Government का rationale था तीन चीज़ें: black money eliminate करना, fake currency बंद करना, और digital payments को promote करना.

Short-term reality बहुत harsh थी. Banks और ATMs के बाहर घंटों, कभी-कभी days की lines. Cash की severe shortage. Small businesses जो mostly cash में operate करते थे, उनका बुरा हाल था. Daily wage workers जिनकी पूरी economy cash में थी, वो सबसे ज़्यादा suffer किए. किसान जो अपनी crops बेचकर आए थे, उनके पास cash था लेकिन वो useless हो गया था.

Long-term outcomes पर debate है. RBI के data के अनुसार 99% से ज़्यादा notes वापस आए, जो critics के लिए यह prove करता था कि black money उतना नहीं था. GDP growth 2016-17 में थोड़ी slow हुई. लेकिन digital payments ने jump लिया. UPI का adoption तेज़ हुआ. Tax base expand हुआ.

यह एक controversial decision है जिस पर economists अभी भी agree नहीं करते. यह एक perfect example है कि एक economic decision के multiple और competing effects होते हैं.

COVID-19 का झटका और Recovery

2020 में COVID-19 pandemic आई. India ने March 2020 में एक strict nationwide lockdown लगाया जो कई phases में months तक चला. Factories बंद, shops बंद, transport बंद, offices बंद.

2020-21 में India की GDP -7.3% हुई. यह independent India के history में सबसे बड़ी GDP contraction थी. Crores लोगों की jobs गईं. Construction workers, auto-rickshaw drivers, street vendors, domestic workers, यह सब severely affect हुए.

जो images India को सबसे ज़्यादा hurt किया वो थे migrant workers का पैदल घर लौटना. Millions of people जो cities में factories में काम करते थे, suddenly jobless हो गए. Trains बंद थीं. बहुत लोग hundreds of kilometers पैदल चले, कुछ रास्ते में ही मर गए.

Government ने response में क्या किया: PM Garib Kalyan Anna Yojana launch की जिसमें 80 crore लोगों को free ration दिया. MNREGA में ज़्यादा spending की. Infrastructure projects तेज़ किए ताकि construction jobs बनें.

Recovery: 2021-22 में GDP 8.7% grow की. Vaccine production में India ने miracle perform किया. Serum Institute of India ने Covishield बनाई, Bharat Biotech ने Covaxin. India ने 90 से ज़्यादा countries को vaccines supply किए. यह India की pharmaceutical industry की world-class capability का proof था.

Green Revolution: जब India ने खुद को food secure किया

1960s में India एक बहुत different situation में था. Droughts और floods की वजह से food production कम था. India food के लिए America पर depend था. इसे PL-480 program कहते थे. यह dependence humiliating भी था और economically vulnerable भी.

तब Dr. MS Swaminathan और उनकी team ने, Norman Borlaug की high-yield wheat varieties को India में adapt करके, Green Revolution शुरू किया. Punjab, Haryana, और western UP में नई varieties of wheat और rice, better fertilizers, और irrigation के साथ production dramatically बढ़ी.

1965-66 में India का wheat production 10 million tonnes था. 1978-79 तक यह 31 million tonnes हो गया. India न सिर्फ food self-sufficient हो गया बल्कि exporter भी बन गया. यह एक economic और social revolution था.

लेकिन Green Revolution के long-term costs भी थे. Punjab और Haryana में groundwater बहुत तेज़ी से use हुआ. अब बहुत areas में water table बहुत नीचे चला गया है. Chemical fertilizers के ज़्यादा use से soil health affect हुई. यह एक trade-off था जिसका असर अभी भी है.

भाग 6

Resources, Decisions और Trade-offs

कल्पना करो तुम्हारे गाँव के बाहर एक बड़ी ज़मीन है जहाँ एक घना जंगल है. एक दिन government की survey team आती है और announce करती है कि ज़मीन के नीचे iron ore का बहुत बड़ा deposit है. गाँव में खुशी की लहर दौड़ जाती है. लेकिन फिर सवाल आते हैं: जंगल का क्या? वहाँ रहने वाले लोगों का क्या? Ore निकालने से क्या फायदा होगा, किसे होगा, और क्या नुकसान होगा?

यह काल्पनिक नहीं है. India में यह scenario बार-बार दोहराया गया है. Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh में खनिज resources हैं, जंगल हैं, आदिवासी communities हैं, और development का pressure है.

India के Natural Resources: क्या है हमारे पास?

Coal: India में दुनिया का 4th largest coal reserve है. Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, और West Bengal में बड़े deposits हैं. India अपनी electricity का करीब 70% अभी भी coal से बनाता है. Coal India Limited दुनिया की सबसे बड़ी coal mining company है.

Iron Ore: Odisha, Jharkhand, और Chhattisgarh में बड़े iron ore deposits हैं. India दुनिया का 4th largest iron ore producer है. इसी से steel बनती है जो construction और manufacturing के लिए essential है. Tata Steel और SAIL जैसी companies इसी पर depend करती हैं.

Lithium: 2023 में Geological Survey of India ने Rajasthan के Degana area में 5.9 million tonnes का lithium deposit discover किया. यह बहुत significant है क्योंकि India अभी lithium import करता था जो electric vehicles और phone batteries में लगता है. India का EV push इसी lithium पर partially depend करेगा.

Water: Freshwater एक बहुत underrated resource है. India में Ganga, Brahmaputra, और Godavari जैसी बड़ी rivers हैं. लेकिन groundwater over-exploitation एक serious problem है. कई states में water table बहुत नीचे जा चुकी है.

Fertile Land: India में 160 million hectares agricultural land है. Indo-Gangetic plain, जो Punjab से Bengal तक फैली है, दुनिया की सबसे fertile plains में से एक है. यह India की food security की foundation है.

Value Addition: Raw से Refined तक

एक बहुत important economic concept है: जितना ज़्यादा processing करो, उतनी ज़्यादा value create होती है. इसे value addition कहते हैं.

> **Milk to Paneer to Cheesecake:** एक litre raw milk की value: करीब ₹60. उससे बना paneer: ₹200-250 मूल्य. उस paneer से बनाया palak paneer restaurant में: ₹350-400 per dish. उसी milk से western cheesecake बना दो किसी fancy restaurant में: ₹600-800 per slice. Original milk उतना ही है, लेकिन हर step में value add होती है. यही principle country level पर work करता है.

India का Iron Ore Example: अगर India raw iron ore export करे, तो शायद $50-60 per tonne मिले. अगर उसे process करके pig iron बनाए, तो $200 per tonne. अगर steel बनाए, तो $500-600 per tonne. अगर से automobile parts बनाए, तो value और ज़्यादा. हर step में value बढ़ती है, और हर step में jobs बनती हैं.

यही reason है कि economists और policymakers चाहते हैं कि India सिर्फ raw material exporter न रहे, बल्कि manufactured goods exporter बने. Make in India इसी का implementation है.

Trade-off: कोई free lunch नहीं होता

Economics का एक सबसे fundamental principle है: TANSTAAFL. There Ain't No Such Thing As A Free Lunch. हर decision की एक cost होती है. जो cost directly दिखती नहीं, वो opportunity cost होती है.

Opportunity cost का मतलब है: जो best alternative तुमने नहीं चुना, उसकी value.

Personal level पर: तुम्हारे पास 3 घंटे हैं. तुम cricket खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, या दोस्तों के साथ बैठ सकते हो. अगर cricket खेला, तो reading और friends की opportunity cost है. सबसे valuable alternative choose करो.

Policy level पर: Government के पास budget है ₹100. वो ₹100 roads पर लगाए, hospitals पर, schools पर, या defense पर? अगर roads पर लगाए, तो hospitals की opportunity cost है. अगर सब schools पर, तो roads की. Perfect allocation नहीं होती. Priorities decide करनी पड़ती हैं.

> **India का Real Trade-off: Coal vs. Clean Energy:** India को electricity की बहुत ज़रूरत है. 300 million लोगों के घरों में अभी भी regular, reliable electricity नहीं है. Coal से सस्ती और reliable electricity आती है. Coal mines में lakhs of people काम करते हैं. लेकिन coal जलाने से India के cities दुनिया के सबसे polluted हो गए हैं. Delhi, Kanpur, Patna consistently world pollution index में top पर रहते हैं. Air

pollution से India में हर साल लाखों लोग early death से मरते हैं. Solar और wind energy clean हैं लेकिन अभी भी coal से ज़्यादा expensive हैं और consistent नहीं हैं. अगर coal बंद करें: environment better होगी, लेकिन lakhs of miners की jobs जाएंगी, electricity expensive होगी. अगर coal continue करें: jobs रहेंगी, electricity सस्ती रहेगी, लेकिन pollution continue. यह है real trade-off. कोई easy answer नहीं.

Sustainable Development: आज और कल का **balance**

Sustainable development का concept 1987 में Brundtland Commission ने define किया था: 'Development जो present की needs पूरी करे without compromising future generations की ability to meet their own needs.'

India के context में इसका practical मतलब:

Ganga का example: Ganga river पर 500 million से ज़्यादा लोग depend करते हैं. Factories और cities ने decades तक उसमें waste dump किया. आज Ganga बहुत polluted है. Namami Gange program इसे clean करने की कोशिश है. लेकिन अगर industrial discharge पर strict limits लगाओ तो कुछ factories बंद होंगी, jobs जाएंगी. Short-term economic cost vs. long-term environmental benefit.

Fisheries: India की coastal communities fishing पर depend करती हैं. लेकिन overfishing की वजह से fish populations घट रहे हैं. अगर आज बहुत मछली पकड़ी, तो future में कम होगी. Sustainable fishing practices future की food security protect करती हैं.

भाग 7

Government और Economy

Market बहुत सी चीज़ें efficiently करता है. लेकिन कुछ चीज़ें market अकेले नहीं कर सकता. यहाँ government आती है. और India जैसे बड़े, diverse, और developing देश में government का economic role बहुत बड़ा है.

Government Market में क्यों दखल देती है?

Market failures: कभी-कभी free market अच्छे outcomes नहीं देता. कुछ classic examples:

Public Goods: Roads, national defense, street lights. इनसे सबको benefit मिलता है और कोई एक person को इनसे exclude नहीं किया जा सकता. अगर government इन्हें न बनाए तो market नहीं बनाएगा क्योंकि इनसे individual profit नहीं होता.

Externalities: जब किसी की activity का असर दूसरों पर पड़े और वो cost या benefit price में reflect न हो. एक factory pollution करती है. उसकी cost factory की price में नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों की health पर है. Government को regulate करना पड़ता है.

Inequality: Market efficient हो सकता है लेकिन fair नहीं होता. जो पहले से better position में हैं वो और आगे जाते हैं. Government taxes और welfare programs से redistribute करती है.

India में Taxes: पैसा कहाँ से आता है?

Government का पैसा taxes से आता है. India में कुछ major taxes:

Income Tax: जो लोग एक limit से ज़्यादा कमाते हैं वो income का percentage government को देते हैं. India में करीब ₹2.5 lakh तक income tax-free है. उससे ज़्यादा पर 5% से शुरू होकर ₹10 lakh से ज़्यादा income पर 30% तक tax है. जितना ज़्यादा कमाओ, उतना ज़्यादा rate. इसे progressive taxation कहते हैं.

GST: Goods and Services Tax जो 2017 में आया. यह एक uniform indirect tax है जो पूरे India में apply होता है. इससे पहले हर state के अलग taxes थे और interstate trade complicated था. GST ने इसे simplify किया. अलग-अलग चीज़ों पर अलग GST rates हैं: ज़रूरी चीज़ें जैसे food grains पर zero, और luxury goods पर 28%.

Corporate Tax: Companies अपने profits पर tax देती हैं. 2019 में government ने corporate tax rate cut किया ताकि ज़्यादा investment आए.

GST का Real Example: अगर तुम किसी restaurant में जाते हो और खाने का bill ₹200 है, तो 5% GST लगेगा यानी ₹10 extra. Total ₹210 देना होगा. वो ₹10 government के पास जाता है. एक expensive hotel में यह rate 18% होगा. इसी तरह every product पर tax है. बिस्कुट पर 18%, branded clothes पर 12%, दाल-आटा पर 0%. Idea यह है कि ज़रूरी चीज़ें सस्ती रहें, luxury items से ज़्यादा revenue आए.

Government के बड़े Welfare Programs

India में कुछ programs हैं जो directly करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को affect करते हैं:

PM Garib Kalyan Anna Yojana: 80 crore से ज़्यादा लोगों को free ration. यह दुनिया का सबसे बड़ा food security program है. COVID में शुरू हुआ, continue हुआ. इसका economic logic: अगर poor people का food secure है, तो वो जो थोड़ी income है उसे दूसरी ज़रूरतों पर लगा सकते हैं. यह spending economy में multiplier effect create करती है.

MNREGA यानी Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: Rural areas में हर घर को साल में 100 दिन का guaranteed paid work. Rate ₹200-300 per day तक state-dependent है. Drought या off-season में जब agricultural work नहीं होता, यह scheme बहुत important safety net है. 2005 में launch हुई, आज भी relevant है.

Ayushman Bharat: Economically vulnerable families को ₹5 lakh per year का health insurance. Empanelled hospitals में cashless treatment. India में medical bills एक major reason है जिससे families poverty में जाती हैं. यह scheme उसे address करती है. 2018 में launch हुई.

PM Kisan Samman Nidhi: Small और marginal farmers को ₹6,000 per year directly bank account में. यह direct income support है जो middleman के बिना जाता है. DBT यानी Direct Benefit Transfer के ज़रिए.

Budget: देश की सालाना planning

हर साल 1 February को Finance Minister Parliament में Union Budget present करती हैं. यह देश की सालाना economic planning है. इसमें बताया जाता है:

Revenue: Government इस साल कितना taxes collect करेगी और कहाँ से.

Expenditure: इस साल कहाँ कितना खर्च होगा. Education, health, defense, infrastructure, subsidies.

Fiscal Deficit: अगर खर्च ज़्यादा है income से, तो difference को fiscal deficit कहते हैं. Government इस gap को bonds issue करके यानी loan लेकर fill करती है.

India का fiscal deficit control में रखना important है. बहुत ज़्यादा borrowing करने से future में interest payments बढ़ती हैं जो दूसरे programs के लिए कम पैसा छोड़ती हैं. यह intergenerational equity का issue है, आज का debt future generations चुकाती हैं.

Infrastructure: Growth की रीढ़

किसी भी country की economic growth के लिए infrastructure बहुत ज़रूरी है. Roads, railways, airports, ports, electricity, और internet. बिना इनके business होना मुश्किल है.

India में infrastructure पर historically कम investment हुई थी. लेकिन पिछले दशक में National Highway network बहुत expand हुआ. नए airports बने. Metro systems कई शहरों में हैं. Dedicated Freight Corridors बन रहे हैं जो manufacturing को बहुत boost देंगे.

Infrastructure investment का multiplier effect होता है. एक highway build करने में workers को jobs मिलती हैं. वो highway बनने के बाद transport faster और cheaper होता है. Businesses grow करते हैं. Jobs और बनती हैं. Tax revenue बढ़ता है. एक investment कई बार return देती है.

India's Digital Public Infrastructure

India ने एक unique digital public infrastructure बनाई है जिसे India Stack कहते हैं. यह Aadhaar, UPI, और DigiLocker का combination है.

Aadhaar: 1.3 billion Indians को unique biometric identity. इससे government benefits directly target हो सकते हैं. Fake identities और ghosts beneficiaries eliminate हुए. DBT यानी Direct Benefit Transfer से करोड़ों का पैसा middlemen को bypass करते हुए directly लोगों के accounts में जाता है.

यह system दुनिया में unique है. World Bank ने इसे एक model बताया है. कई developing countries India से यह सीखना चाहते हैं. यह India की एक बड़ी soft power success है.

> **PM Jan Dhan Yojana:** 2014 में launch हुई यह scheme India की financial inclusion की सबसे बड़ी drive थी. 50 crore से ज़्यादा zero-balance bank accounts खुले. Millions of families जिनके पास कोई bank account नहीं था, पहली बार formal banking system में आए. COVID में जब government ने cash transfer करना था, यह accounts काम आए. Infrastructure तैयार थी तो benefit directly पहुँचा.

भाग 8

दुनिया से India का Connection

India एक island नहीं है. दुनिया के बाकी देशों से हमारे गहरे economic ties हैं. Trade, investment, migration, technology, सब directions में flows हैं. एक देश में होने वाली घटना India को affect करती है, और India में होने वाली events दूसरों को affect करती हैं.

इसे globalization कहते हैं. यह process decades से चल रही है और अब इतनी deep है कि इससे बाहर निकलना किसी भी देश के लिए possible नहीं है.

India क्या बेचता है, क्या खरीदता है?

India के Exports: IT और software services सबसे बड़ा export है. Infosys, TCS, Wipro, HCL ये सब American और European companies के लिए software बनाती हैं, यह invisible export है. Pharmaceuticals: India दुनिया का सबसे बड़ा generic medicine exporter है. WHO-listed medicines का 20% India से आता है. Textiles और garments, jewellery, engineering goods, rice (India दुनिया का सबसे बड़ा rice exporter है), और spices.

India के Imports: Oil और natural gas सबसे बड़ा import है. India को 85% oil import करना पड़ता है. इसके बाद electronics और electronic components (mostly China से), machinery, fertilizers (Russia और Belarus से), और gold (Indians को gold पसंद है).

Trade Balance: अगर export ज़्यादा हो तो trade surplus, import ज़्यादा हो तो trade deficit. India में generally trade deficit रहता है, specially oil import की वजह से. इसे finance करने के लिए IT services से आने वाली dollars और remittances help करती हैं.

Dollar क्यों सब कुछ है?

International trade में एक problem है: हर देश की अपनी currency है. जब India और Japan trade करते हैं, तो कौन सी currency use होगी? Yen या Rupee? इस problem का solution यह हुआ कि world ने एक common reference currency adopt की: US Dollar.

Oil, gold, और ज़्यादातर global trade dollar में होती है. इसे dollar dominance या petrodollar system कहते हैं. इसका मतलब है:

- India को dollars की ज़रूरत है trade के लिए.
- जब dollar strong होता है यानी ₹1 dollar के लिए ज़्यादा rupees लगें, तो India का import bill बढ़ता है.
- RBI को forex reserves maintain करने पड़ते हैं जो crisis में काम आएं.

2022 का Example: Russia-Ukraine war हुई. Oil prices बढ़े क्योंकि Russia एक major oil supplier है. Dollar strong हुआ क्योंकि investors safe haven की तरफ गए. India को oil के लिए ज़्यादा dollars देने पड़े. Rupee weaken हुआ. Petrol महंगा हुआ. CNG महंगी हुई. Auto-rickshaw fare बढ़े. Vegetables महंगी हुईं क्योंकि transport cost बढ़ी. एक दूसरे continent में हुई war का असर तुम्हारे रोज़मर्रा के खर्च पर पड़ा.

India और Russia का Oil Deal

Russia-Ukraine war के बाद USA और Europe ने Russia पर severe economic sanctions लगाए. Russian oil को boycott किया. कुछ Western companies ने Russia छोड़ा. यह Russia को economically isolate करने की कोशिश थी.

India ने एक अलग decision लिया. India ने Russia से discounted rate पर oil खरीदना जारी रखा. क्यों? क्योंकि Russia oil बहुत सस्ते में दे रहा था, $10-20 per barrel discount के साथ. India जैसे developing country के लिए यह बहुत valuable था.

America और Europe ने pressure डाला. India ने diplomatically कहा: हम अपने लोगों के benefit में decision लेते हैं. India की विदेश नीति है Strategic Autonomy, यानी हम किसी भी camp में officially नहीं हैं.

Economic outcome: India को billions of dollars की savings हुई. Domestic petrol prices उतनी नहीं बढ़ीं जितनी बढ़ सकती थीं. यह decision economically India के लिए beneficial था, politically complicated था. यह real world economics है.

Remittances: Gulf का connection

India के lakhs लोग Gulf countries में काम करते हैं. UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain. यह mostly construction workers, drivers, domestic helpers, और cooks हैं. वो अपनी income का बड़ा हिस्सा India भेजते हैं.

India दुनिया में सबसे ज़्यादा remittances receive करने वाला देश है. 2023 में $125 billion से ज़्यादा. यह India की total merchandise exports से भी ज़्यादा है. और यह directly families तक पहुँचता है, बिना किसी middleman के.

Kerala, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Andhra Pradesh, और Tamil Nadu में सबसे ज़्यादा Gulf workers हैं. Kerala की economy तो इतनी Gulf-dependent है कि जब Gulf में oil price गिरती है, Kerala में construction और consumption कम हो जाती है. यह external economic dependence है.

लेकिन एक flip side भी है. जो लोग Gulf जाते हैं, वो अपने families से दूर रहते हैं. Social cost बहुत है. और Gulf countries में Indian workers को often कम rights मिलते हैं, better treatment के लिए struggles होती हैं.

India और **China: Complicated Relationship**

India का China के साथ economic relationship बहुत complicated है. China India का सबसे बड़ा trading partner है लेकिन साथ ही एक major competitor और geopolitical rival भी है.

India China से क्या import करता है: Electronics, mobile phones (especially components), machinery, chemicals, और toys. India का China के साथ trade deficit बहुत बड़ा है, हम उनसे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं जितना बेचते हैं.

यह dependence problematic है. जब COVID में China की factories बंद हुईं, India में भी manufacturing disrupted हुई क्योंकि components नहीं आए. इसीलिए India अब China के alternatives develop करने की कोशिश कर रहा है. PLI यानी Production Linked Incentive scheme इसी के लिए है, domestic manufacturing को incentivize करने के लिए.

FDI: जब दुनिया **India** में **Invest** करती है

FDI यानी Foreign Direct Investment वो है जब कोई foreign company India में directly invest करती है. Factory लगाए, office खोले, या existing company में stake ले.

Apple ने India में iPhone manufacturing शुरू की है. Samsung का production plant है. Amazon और Walmart ने billions invest किए हैं. Google ने $10 billion invest करने का announcement किया था. यह सब FDI है.

FDI से capital, technology, और know-how आता है. Jobs बनती हैं. Local businesses suppliers बनते हैं जिससे domestic industry develop होती है. Government को tax revenue मिलता है.

India और **China: Complicated Relationship**

India का China के साथ economic relationship बहुत complicated है. China India का सबसे बड़ा trading partner है लेकिन साथ ही एक major competitor और geopolitical rival भी है.

India China से क्या import करता है: Electronics, mobile phones के components, machinery, chemicals. India का China के साथ trade deficit बहुत बड़ा है. हम उनसे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं जितना बेचते हैं.

यह dependence problematic है. COVID में China की factories बंद हुईं, India में manufacturing disrupted हुई. PLI यानी Production Linked Incentive scheme इसी का जवाब है, domestic manufacturing को incentivize करने के लिए. Apple, Samsung, और दूसरे brands को India में बनाने के लिए incentives दिए जा रहे हैं.

India का Diaspora: Global Indians

India का diaspora, यानी दुनिया भर में रहने वाले Indian-origin लोग, एक बहुत powerful economic force है. 3 crore से ज़्यादा लोग India से बाहर हैं. Gulf में workers, UK में doctors, America में tech professionals, Canada में students.

Indian diaspora बहुत successful है. America में Indians सबसे educated और highest-earning ethnic group में हैं. यह India की human capital की quality दिखाता है. लेकिन यह brain drain भी है. India ने इनकी education में invest किया, talent बाहर चला गया.

Solution यह है कि India में enough opportunities हों ताकि talented लोग यहीं रहें या वापस आएं. Startup ecosystem, better research facilities, और quality of life में improvement इस direction में important steps हैं.

> **Trade Agreements:** India कुछ Free Trade Agreements यानी FTA कर रहा है. UAE के साथ CEPA हुआ. Australia के साथ interim FTA हुआ. UK के साथ negotiations चल रही हैं. FTA में दोनों countries एक-दूसरे के goods पर tariffs कम करती हैं जिससे trade बढ़ता है. लेकिन FTA में भी winners और losers होते हैं. Domestic industries जो compete नहीं कर सकतीं, उन्हें नुकसान होता है.

भाग 9

खबर पढ़ना सीखो

अब तक तुमने theory पढ़ी, case studies देखे, India और दुनिया के connections समझे. अब एक ऐसी skill सीखते हैं जो हर रोज़ काम आएगी: economic news पढ़ना और actually समझना.

News हर रोज़ आती है. TV पर, phone पर, newspaper में. लेकिन ज़्यादातर लोग news सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. एक curious mind रुककर सोचता है: यह क्यों हुआ? इसका असर क्या होगा? इसका मुझसे या मेरी community से क्या connection है?

Headlines को **critically** पढ़ो

एक headline पढ़ो: 'India की GDP 7% बढ़ी.'

पहली reaction: वाह, India आगे बढ़ रहा है. Good news है.

लेकिन एक critical reader के सवाल:

> Compared to क्या? पिछले साल GDP 9% थी तो 7% actually slowdown है.
>
> Real GDP या Nominal? अगर GDP 7% बढ़ी और inflation 5% है, तो real growth सिर्फ 2% है.
>
> किसकी GDP बढ़ी? क्या rural areas में भी growth है? क्या जो सबसे गरीब हैं उन तक growth पहुँची?
>
> Per capita क्या है? Population भी बढ़ रही है, इसलिए total GDP बढ़ना काफी नहीं है.

यह 'critical thinking' है. हर headline के पीछे more questions हैं. Good citizens वो हैं जो सिर्फ headline नहीं पढ़ते, उसे challenge करते हैं.

एक **Article** को **Analyze** करते हैं

> HEADLINE: Global Shipping Costs बढ़े, India में Inflation का डर
>
> Middle East में ongoing conflict की वजह से Red Sea route, जो Europe और Asia को connect करता है, पर commercial shipping बहुत risky हो गई है. Major shipping companies अपने vessels को Suez Canal के बजाय अब Africa के Cape of Good Hope का लंबा रास्ता ले जा रही हैं. इससे shipping time 10-14 दिन बढ़ गया है और cost 2-3 गुना हो गई है. India जो crude oil, electronics, और industrial goods import करता है, उनकी landed cost बढ़ रही है. Economists का कहना है कि

अगर यह situation 2-3 महीने continue रही तो CPI inflation पर 0.3-0.5% का असर पड़ सकता है.

अब step by step analyze करते हैं:

Background: Middle East conflict. Red Sea route risk हुई.

Direct economic effect: Shipping time और cost बढ़ी.

India specific impact: Import cost बढ़ी.

Downstream effect: India में CPI inflation बढ़ सकती है.

What's NOT in the article: कौन से specific goods most affected होंगे? Domestic Indian industry को क्या opportunity हो सकती है? क्या RBI को policy change करना होगा?

अब personal connection: तुम्हारे घर में जो imported electronics हैं, जो petrol है, जो imported materials से बनी चीज़ें हैं, वो महंगी होंगी. एक geopolitical event का chain reaction तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक पहुँचता है.

Dono Sides Dekhna Seekho

हर economic policy और decision में winners और losers होते हैं. Good analysis दोनों को देखती है.

Minimum Wage बढ़ाने का example: Government decide करे कि minimum wage ₹400 per day से बढ़ाकर ₹600 per day होगी.

Workers का perspective: बहुत अच्छा. हमारी income बढ़ेगी. जीवन स्तर बेहतर होगा.

Small Business Owner का perspective: मेरी labour cost 50% बढ़ गई. या तो prices बढ़ाऊं या कुछ workers की छुट्टी करूं या automation करूं.

Economist का perspective: Short-term में कुछ jobs जा सकती हैं लेकिन workers की spending power बढ़ने से demand बढ़ेगी जो ultimately more business create कर सकती है. Long-term में यह complex है.

Government का perspective: Social equity ज़रूरी है. लेकिन business climate भी maintain करना है.

कौन सही है? सब के arguments में merit है. एक good economist, journalist, या informed citizen सबको consider करता है before forming an opinion.

Habit बनाओ: जब भी कोई economic news पढ़ो, तीन सवाल पूछो। एक: क्या हुआ और क्यों? दो: किस पर क्या असर पड़ा? तीन: क्या मैं दोनों या सभी sides देख रहा हूँ?

> यह habit बनाने में time लगता है लेकिन यही critical thinking है जो एक informed citizen और future में एक better decision-maker बनाती है.

Dollar Digest पढ़ो

यह सब सिर्फ एक किताब तक limited नहीं है. असली दुनिया में हर हफ्ते नई economic stories आती हैं. Tariffs, RBI decisions, corporate results, global events, हर हफ्ते कुछ नया होता है जो India की economy को affect करता है.

Dollar Digest उन stories को simple language में explain करता है. बिना complicated jargon के, सीधे point पर. Articles, videos, और analysis जो तुम्हें informed रखें.

dollardigest.in पर जाओ. वहाँ India और दुनिया की economic news पढ़ो. अब जब तुम यह किताब पढ़ चुके हो, वो articles तुम्हें सिर्फ information नहीं देंगे, तुम उन्हें actually analyze कर पाओगे.

Glossary: मुश्किल शब्दों के आसान मतलब

Barter System: जब पैसे नहीं थे और लोग चीज़ें आपस में बदलते थे.

Double Coincidence of Wants: Barter में दोनों लोगों को एक-दूसरे की चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए. यह हमेशा possible नहीं था.

Demand: लोग किसी चीज़ को कितना खरीदना चाहते हैं, और किस price पर.

Supply: Sellers के पास कितना है बेचने के लिए, और किस price पर.

Equilibrium: वो price जहाँ demand और supply बराबर हों. Market naturally यहाँ पहुँचता है.

Inflation: समय के साथ चीज़ों की overall कीमत का बढ़ना. महंगाई.

Deflation: जब prices overall गिरने लगें. Economy के लिए यह भी हानिकारक हो सकता है.

Hyperinflation: जब inflation बहुत बहुत ज़्यादा हो, जैसे Zimbabwe में 2008 में.

CPI: Consumer Price Index. एक typical family की जो चीज़ें होती हैं उनकी average price को track करने का तरीका.

GDP: Gross Domestic Product. एक साल में पूरे देश की total economic output की value.

Per Capita GDP: GDP को total population से divide करने पर मिली value. Average income per person.

RBI: Reserve Bank of India. India का central bank. Currency issue करता है, inflation control करता है.

Repo Rate: वो rate जिस पर RBI commercial banks को loan देती है. Inflation control करने का मुख्य tool.

Fiscal Deficit: जब government का खर्च उसकी income से ज़्यादा हो.

Natural Resource: Nature की बनाई चीज़ें जैसे coal, oil, water, fertile land जिनकी economic value हो.

Value Addition: Raw material को process करके उसकी value बढ़ाना.

Opportunity Cost: जो चीज़ तुमने नहीं चुनी उसकी value. हर decision की असली कीमत.

Export: अपने देश से दूसरे देशों को goods या services बेचना.

Import: दूसरे देशों से अपने देश में goods या services खरीदना.

Trade Deficit: जब import, export से ज़्यादा हो.

Remittances: विदेश में काम करने वाले लोग जो पैसा घर भेजते हैं.

Sustainable Development: आज की ज़रूरत पूरी करो लेकिन future generations के लिए resources बचाओ.

Globalization: दुनिया के देशों का trade, technology, और migration के ज़रिए एक-दूसरे से जुड़ना.

Demonetization: पुरानी currency notes को बंद करके नई लाना. India में 2016 में हुआ.

UPI: Unified Payments Interface. India का instant digital payment system जिसे पूरी दुनिया देख रही है.

Sanctions: जब एक देश दूसरे को punish करने के लिए उससे trade या financial dealings बंद करे.

License Raj: 1991 से पहले India में वो system जहाँ हर business activity के लिए government license ज़रूरी था.

Liberalization: Economy को open करना, restrictions हटाना. India ने 1991 में किया.

Supply Chain: वो पूरी chain जिससे raw material processing से होकर final product customer तक पहुँचता है.

GST: Goods and Services Tax. 2017 में लागू हुआ India का uniform indirect tax system.

Monetary Policy: RBI के वो decisions जो money supply और interest rates को affect करें.

Fiscal Policy: Government के budget decisions जो taxation और spending को affect करें.

Subsidy: जब government किसी चीज़ की price artificially कम रखने के लिए खुद उसका कुछ खर्च उठाए.

Green Revolution: 1960s में India में agricultural technology revolution जिसने food production dramatically बढ़ाई.

Purchasing Power: एक निश्चित amount of money से कितना खरीद सकते हो.

Dollar Digest

dollardigest.in

Economy की दुनिया, सबके लिए.

यह किताब *Dollar Digest* की *community outreach initiative* का हिस्सा है.